प्रेस कॉन्फ्रेंस

शिक्षा विभाग, पटना
बिहार सरकार

1. उद्देश्य– शिक्षा विभाग, बिहार का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक छात्र को सुलभ गुणवत्तापूर्ण, समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा प्रदान कर मानव संसाधन का विकास करना तथा बिहार को ज्ञान कौशल और नवाचार आधारित प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करना है।
2. शिक्षा पर व्यय :–

	2005	2025
शिक्षा पर व्यय	4341 करोड (चार हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ रूपये)	72,652.44 करोड (बहत्तर हजार छह सौ बावन करोड़ चौवालिश लाख रूपये)

3. सात निश्चय–3

माननीय मुख्यमंत्री "सात निश्चय–3" के अंतर्गत चतुर्थ निश्चय – "उन्नत शिक्षा, उज्ज्वल भविष्य" के तहत शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य शीघ्रता से क्रियान्वित किए जा रहे हैं—

(क) प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना।

प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय को चिह्नित करते हुए उसे आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित एवं विकसित किया जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना।

राज्य के ऐसे प्रखंडों, जहाँ वर्तमान में डिग्री महाविद्यालय उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ नये डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी।

(ग) नये उच्च शिक्षा विभाग का गठन।

नये उच्च शिक्षा विभाग के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की जा चुकी है तथा विभाग के स्थायी पदों के सृजन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएँ प्रगति पर हैं।

(घ) पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना।

राज्य के पुराने एवं प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों को "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कार्ययोजना तैयार कर उपयुक्त संस्थानों का चयन किया जा रहा है।

(ङ) एक नये एजुकेशन सिटी का निर्माण करना।

राज्य में एक नये "एजुकेशन सिटी" के निर्माण हेतु विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

4. नियुक्ति

- विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति :–
  - राज्य सरकार द्वारा **सरकारी विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम तीन चरणों में कुल 2,27,195 (दो लाख सत्ताईस हजार एक सौ पंचान्नवे) विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति कर ऐतिहासिक समय में योगदान करा दिया गया है,** जो देश के लिए एक मिसाल है और राज्य को गौरवान्वित करता है।
  - बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 28,748 प्रधान शिक्षक एवं 4,699 प्रधानाध्यापक नियुक्त की गई है।
- अनुकम्पा नियुक्ति
  - राज्य के प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मृत आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली 2025 एवं बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली 2025

अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के अधिसूचित होने के पश्चात् अभी तक कुल 5073 विद्यालय लिपिक एवं 541 विद्यालय परिचारी अर्थात् कुल 5614 आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की गयी है।

- <u>प्रक्रियाधीन नियुक्ति :–</u>

  – नवसृजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पद पर नियुक्ति हेतु BPSC को अधियाचना प्रेषित।

  – विशेष विद्यालय अध्यापक के 7279 पद पर नियुक्ति हेतु BPSC को अधियाचना प्रेषित।

  – TRE-4 के तहत विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 31 जिलों से आरक्षण रोस्टर पंजी जिलों से समाशोधन होने के पश्चात् प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी जांच प्रक्रियाधीन है। जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में बिहार लोक सेवा आयोग को विज्ञापन प्रकाशन हेतु अधियाचना भेज दी जायेगी।

- सक्षमता परीक्षा

  – बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित अभी तक चार चरणों में स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें कुल 319747 शिक्षक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए तथा कुल 266786 शिक्षक अभ्यर्थी सफल घोषित हुए है। सक्षमता परीक्षा (पंचम) के लिए ऑनलाईन आवेदन दिनांक 31.12.2025 से 09.01.2026 के बीच भरा जायेगा।

<u>नियुक्ति – उच्च शिक्षा</u>

अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति

- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए कुल 2849 सहायक प्राध्यापकों की अनुशंसा भेजी गई है।
- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) द्वारा कुल 2983 पदों के लिए अनुशंसा भेजी गई है।

- इस प्रकार राज्य के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए कुल 5832 सहायक प्राध्यापकों के पदो के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है।
- राज्य के सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय में 116 प्राचार्यो की नियुक्ति की गई।

5. सकारात्मक प्रभाव **(Positive Impact)** :–

- **2005** से **2024 के मध्य** सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के बाद **अध्यापकों की संख्या में 187 प्रतिशत वृद्धि हुई है।**

	2005	**2025**
शिक्षकों की संख्या	**2.04** लाख	**5.87** लाख

- विद्यालीय शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात

छात्र शिक्षक अनुपात	**2005**	**2025**
	65:1	**29 :1**

- <u>साक्षरता दर</u>

	2001 की जनगणना		2011 की जनगणना		2023 जाति जनगणना	
साक्षरता दर	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
	60. 32%	33.57%	71.20%	51.50%	84.91%	73.91%

- **2005 में 12.5% बच्चे विद्यालय से बाहर** थे। उन विद्यालय से बाहर के बच्चों को उम्र सापेक्ष कक्षा में पहुँचाने हेतु विभिन्न केन्द्रों यथा–उत्प्रेरण केन्द्र, उन्नयन केन्द्र, प्रयास केन्द्र, उत्थान केन्द्र, तालिमी मरकज एवं विद्यालय चलें केन्द्र की शुरूआत की गयी। जिसके फलस्वरूपः–

	2005	2024
Out of School Children	**12%**	**1%** से भी कम

- शिक्षक प्रशिक्षण **(Teacher Training) :-** वितीय वर्ष 2025–26 में अब तक कुल–273473 (दो लाख तेहत्तर हजार चार सौ तेहत्तर) शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है।
- **बिहार में उच्च शिक्षा में लिंग समानता सूचकांक (Gender Parity Index), जो वर्ष 2015–16 में 0.80 था, वह 2021–22 में बढ़कर 0.92 हो गया है। यह वृद्धि राज्य में महिला शिक्षा को सशक्त करने और लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।**
- **MDM-** **पी० एम० पोषण योजना** के अन्तर्गत राज्य के 68,814 **(सड़सठ हजार आठ सौ चौदह)** विद्यालयों में प्रतिदिन 97,15,924 **(संतानवे लाख पन्द्रह हजार नौ सौ चौबीस)** छात्र–छात्राओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- मिशन निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित बुनियादी साक्षरता एवं संख्याज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy) के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य में मिशन निपुण बिहार कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 3 तक के सभी नामांकित बच्चों में हिन्दी एवं गणित के आधारभूत कौशलों को वर्ष 2026–27 तक सुनिश्चित करना है।
- इनमें बच्चों को उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री (TLM) उपलब्ध कराया गया है एवं शिक्षकों को FLN आधारित प्रशिक्षण दिया गया, कक्षा के प्रभावी एवं व्यवस्थित संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी करते हुए विद्यालय तत्परता कार्यक्रम 'चहक' का क्रियान्वयन प्रमुखता के साथ किया गया है।
- फरवरी 2025 में आयोजित मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2022 की तुलना में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों में सकारात्मक उपलब्धि दर्ज किया गया है। वर्ष 2025 में कक्षा 2 स्तर का पाठ धाराप्रवाह पढ़ने वाले बच्चों की

संख्या में 15 प्रतिशत की प्रगति हुई है, जबकि एक अंक का जोड़ कर पाने वाले बच्चों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

- बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देश का पहला बोर्ड बना जिसे नव प्रयोगों और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों के लिए Prime Minister's Award वित Excellence पद Public Administration से भी सम्मानित किया गया है।
- वर्ष 2024 में बिहार परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में कुल 82.11 प्रतिशत विद्यार्थियों एवं इंटरमीडिएट में कुल 86.48 प्रतिशत विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है।
- निःशुल्क कोचिंग की पहल – वर्ष 2023 से समिति के आदर्श विद्यार्थियों के लिए जेईई (JEE) और मेडिकल (NEET) प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु पटना में निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण (Coaching) और राज्य के 09 प्रखंडीय जिलों में स्थित समिति के क्षेत्रीय कार्यालयों में निशुल्क गैर–आवासीय प्रशिक्षण (Coaching) की शुरुआत की गई है ।
- सैनिक स्कूल नालंदा एवं गोपालगंज के स्थापना व्यय मद में 1.5 करोड़ के स्थान पर रू0 3.0 करोड़ की वृद्धि करते हुए प्रतिवर्ष प्रति स्कूल करने तथा इन स्कूल में अध्ययनरत बिहार के छात्रों को पोषाहार मद में प्रति छात्र 45/–रूपये प्रतिदिन के स्थान पर 150/– रूपये प्रतिदिन आर्थिक सहायता में वृद्धि की गयी है।

6. <u>मानदेय में वृद्धि।</u>

- शिक्षा सेवक और शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) का मानदेय ₹11,000 से बढ़ाकर ₹22,000 प्रतिमाह कर दिया गया है, साथ ही ₹1,950 ईपीएफ योगदान भी राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे कुल ₹23,950 प्रतिमाह भुगतान सुनिश्चित हुआ

है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 5% वार्षिक वृद्धि भी दी जाएगी। साथ ही इन्हे स्मार्टफोन खरीदने के लिये 10,000 की सहायता राशि दी जा रही है

- शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय ₹8,000 से बढ़ाकर ₹16,000 कर दिया गया है और उनकी वार्षिक वृद्धि ₹200 से बढ़ाकर ₹400 कर दी गई है।
- रात्रि प्रहरियों का मानदेय ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 किया गया है।
- मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइयों का मानदेय ₹1,650 से बढ़ाकर ₹3,300 कर दिया गया है।

7. <u>शिक्षकों के स्थानांतरण</u>

- विशेष समस्या से ग्रसित 74974 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है एवं 29338 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है।
- स्थानांतरनोंपरान्त ई–शिक्षाकोष पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अंतर जिला स्थानांतरण हेतु प्राप्त 41,689 आवेदकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में 27,171 शिक्षकों को जिला आवंटन की गयी है। 22,928 शिक्षकों द्वारा प्रखंड का च्वाईस दिया गया है जिसमें से 21,307 शिक्षकों का प्रखंड का आवंटन कर दिया गया है। शेष का किया जा रहा है।

8. <u>शिक्षक पे–प्रोटेक्शन (वेतन संरक्षण) एवं शिक्षकों की आपसी वरीयता</u>

- स्थानीय निकाय के शिक्षक जो प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय अध्यापक के रूप में चयनित होकर कार्यरत हैं, को <u>विशिष्ट शिक्षक की भाँति वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।</u> 1,71,987 विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त हो चुका है।

- स्थानीय निकाय शिक्षक (नियोजित शिक्षक), विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता से संबंधित आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22.11.2025 द्वारा निर्गत कर दिया गया है।
- विशिष्ट शिक्षक/विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्यावधि की गणना किया जाएगा।

9. शिक्षा का अधिकार **(Right to Education)**

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में क्षमता के अनुरूप कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत छात्रों का शैक्षणिक सत्र 26–27 में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नामांकन प्रक्रिया को दिनांक 22.12.2025 से प्रारंभ किया गया है। इस सत्र में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अनाथ बच्चों को भी कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों में शामिल किया गया है।
- शैक्षणिक सत्र 2019–20 से प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE 12 (1)(c) के तहत नामांकित कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के 25 प्रतिशत बच्चों के नामांकन के एवज में संबंधित निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति राशि देने हेतु DBT के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों की संख्या 16221 है। ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोडेड कुल 3000 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में जाँच प्रक्रिया पूर्ण हुए 1169 विद्यालयों को 125.71 करोड़ राशि DBT के माध्यम से अंतरित किया गया है। 141 विद्यालयों के जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने पर 9.65 करोड़ राशि DBT के माध्यम से संबंधित विद्यालयों को अंतरण प्रक्रिया में है।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(c) के तहत शैक्षणिक सत्र 2024–25 में 28,465 बच्चों का वर्ग 01 में नामांकन लिया गया है तथा शैक्षणिक सत्र 2025–26 में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कुल 43,168 बच्चों ने वर्ग 01 में नामांकन लिया है।

10. विभिन्न काल्याणकारी योजनाएँ –

Scheme wise disbursement for Year-2025-26 As on dated-22.12.2025					
Sl. No.	**Scheme Name**	**Amount**	**Total Beneficiaries**	**Paid Beneficiaries**	**Total Paid Amount (In Crore)**
1	Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana (Graduation)	Rs 50000	1,98,000	1,98,000	₹ 990.00
2	Mukhyamantri Balika Protsahan Yojana Intermediate	Rs 25000	5,71,694	4,55,714	₹ 1,139.29
3	Mukhyamantri Balika/Balak Protsahan Yojana	Rs 10000	1,14,258	92,002	₹ 92.00
4	Kishori Swasthya	Rs 300	29,12,465	24,50,542	₹ 73.52
5	Mukhayamantri Balak Poshak Yojna SC/ST/BPL(1-8)	Class- 1-5 - Rs 600 Class- 6-8- Rs 700	31,43,228	28,34,691	₹ 179.49
6	Mukhayamantri Balika Poshak Yojna (1-8)		49,96,707	41,33,476	₹ 326.52
7	Mukhayamantri Balika Poshak Yojna (9-12)	Rs 1500	16,85,592	13,59,950	₹ 203.99
8	Mukhayamantri Balak Poshak Yojna APL(1-8)	Class- 1-2 - Rs 400 Class- 3-5 - Rs 500 Class- 6-8- Rs 700	11,72,257	7,19,839	₹ 39.08
9	Mukhayamantri Cycle Yojna	Rs 3000	8,76,581	7,44,401	₹ 223.32
10	Scholarship - General 1 to 8		8,70,413	5,94,767	₹ 103.50
11	Scholarship - General(9-10)	Rs 3600	2,06,229	1,52,613	₹ 46.30
12	Mukhyamantri Bc-Ebc Pre Matric Chhatravriti Yojna	Rs 1800	12,43,541	10,33,091	₹ 185.96
13	Scholarship - BC/EBC 1-8	BC & EBC Welfare	61,77,530	43,19,767	₹ 468.85
14	Mukhyamantri Medhavritti Yojana Matric BC/EBC	Rs 10000	2,29,658	1,84,600	₹ 184.60
15	Pre Matric Scholership for SNA ST Students	Rs 1800	3,45,429	13,313	₹ 2.40
16	Pre Matric Scholership for SNA SC Students	Rs 1800		1,75,318	₹ 12.62
17	Scholarship - SC/ST 1-8	SC & ST Welfare	22,64,403	18,23,971	₹ 190.14
18	Mukhyamantri Medhavritti Yojana Intermediate SC/ST	First Division- Rs 15000 & Second Division Rs 10000	76,679	48,700	₹ 59.26
19	Mukhyamantri Medhavritti Yojana Matric SC/ST	First Division- Rs 10000 & Second Division Rs 8000	1,54,960	1,04,651	₹ 93.82
20	Mukhyamantri Vidyarthi Protsahan Yojana Matric Minority	Rs 10000	61,914	48,623	₹ 48.62
Grand Total :			**2,73,01,538**	**2,14,88,029**	**₹ 4,663.28**

11. <u>केंद्रीय विद्यालय हेतु भूमि की उपलब्धता</u>

- पूर्व से स्वीकृत 53 केंद्रीय विद्यालय में 2 यथा केंद्रीय विद्यालय, मोतिहारी एवं नवादा को भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन।
- भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन 19 केंद्रीय विद्यालय के स्थाई भवन हेतु भूमि चिन्हित है।

12. <u>बालिका शिक्षा</u> (**KGBV**) :

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गतटाइप–I, टाइप–III, एवं टाइप– IV, छात्रावासों में हजारों बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है।

- केजीबीवी टाइप–I (कक्षा VI से VIII) हेतु कुल 390 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें 39,000 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। वर्तमान में 37,359 छात्राएँ नामांकित हैं।
- केजीबीवी टाइप–III (कक्षा VI से XII) हेतु कुल 145 छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें 26,500 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। वर्तमान में 20,443 छात्राएँ नामांकित हैं।
- केजीबीवी टाइप–IV (कक्षा IX से XII) हेतु कुल **139** छात्रावास स्वीकृत हैं, जिनमें से 112 संचालित हैं। इनमें 11,200 छात्राओं की क्षमता के विरुद्ध 8,832 छात्राएँ नामांकित हैं।

13. <u>**PM-SHRI**</u>

- 836 विद्यालयों (यथा– 47 प्रारंभिक एवं 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) के लिए भारत सरकार द्वारा योजना स्वीकृत।

14. <u>टेक्स्ट बुक</u>

- समग्र शिक्षा शैक्षणिक **सत्र 2025–26** हेतु **वर्ग–1 से 8** तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निगम द्वारा कुल **1,19,07,970 सेट अंतर्गत**

12,36,67,188 पुस्तकें मुद्रित करा कर राज्य के सभी प्रखंडों में उपलब्ध करायी गयी। जिसकी कुल लागत **रू0 412.22 करोड़ है।**

- समग्र शिक्षा शैक्षणिक **सत्र 2026–27** हेतु **वर्ग–1 से 8** तक के छात्र–छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निगम द्वारा कुल **1,21,65,487 सेट अंतर्गत 12,81,86,676 पुस्तकें** मुद्रित की जा रही हैं। जिसकी कुल लागत **रू0 407.58 करोड़** है। उक्त कार्य **31 जनवरी 2026** तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **वर्ग–9 से 12 तक की द्विभाषिक** (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) पाठ्य पुस्तकों का निर्माण राज्य के सभी पुस्तकालयों में बच्चों को निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **12,23,864 सेट अंतर्गत 88,73,014 पुस्तकें** मुद्रित की जा रही हैं। जिसकी कुल लागत **रू0 84.98 करोड़** है। उक्त कार्य **10 मार्च 2026** तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

15. डिजिटल सशक्तिकरण एवं प्रशासनिक अनुश्रवण :–

- वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025–26 में राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1,61,138 टैबलेट का वितरण किया गया है जिलावार विवरण संलग्न है। इन टैबलेटों के माध्यम से शिक्षक उपस्थिति, छात्र उपस्थिति तथा प्रधानमंत्री पोषण योजना का रियल–टाइम डिजिटल अनुश्रवण प्रारंभ किये जाने की योजना है। इस व्यवस्था से शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित निर्णयप्रणाली को नई मजबूती मिलेगी।

- ICT लैब एवं स्मार्ट क्लास का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। Digital Initiative के अंतर्गत राज्य के 1,203 प्रारंभिक एवं 784 उच्च माध्यमिक विद्यालयों (कुल 1,987) में ICT Lab (BOOT Model) संचालित है तथा 2,739 प्रारंभिक विद्यालयों में 5,478 Smart Class संचालित हैं।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में 5,277 विद्यालयों में ICT Lab तथा 6,113 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Smart Class स्थापित किए जा रहे हैं।

<u>विज्ञान, नवाचार एवं प्रयोगशालाएँ</u>

- वर्ष 2024–25 में 4,621 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना की गई है,जिसमें से 4,563 विद्यालयों में कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष 3991 माध्यमिक विद्यालयों में इंटीग्रेटेड साइंस लैब की स्थापना हेतु सामग्री की आपूर्ति पूर्ण हो चुका है, जिसमें से 1529 विद्यालयों में लैब अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। साथ ही, 76 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब एवं रोबोटिक्स की स्थापना की गई है।
- वर्ष 2025–26 में 3,478 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Physics Lab, 3,508 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Chemistry Lab एवं 3,478 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Biology Lab के स्थापना एवं संचालन हेतु भवन निर्माण के साथ साथ लैब विकसित करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करायी जा चुकी है।

16. <u>पुस्तकालय</u>

- राज्य में तीन राजकीय एवं 49 अराजकीय वर्गीकृत यथा–07 प्रमण्डलीय, 18 जिला केन्द्रीय पुस्तकालय, 11 अनुमण्डलीय एवं 13 विशिष्ट पुस्तकालय इस प्रकार कुल–52 सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित एवं संचालित है।

17. <u>उच्च शिक्षा</u>

<u>बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजनाः–</u>

- यह योजना **2 अक्टूबर 2016 को "7 निश्चय योजना"** के अंतर्गत शुरू की गई थी।
- इसका लक्ष्य बिहार के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकतम **₹4 लाख** तक का **ब्याज–मुक्त शिक्षा ऋण** उपलब्ध कराया जाता है।

₹2 लाख से अधिक के ऋण के लिए अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 120 माह है और ₹2 लाख तक के ऋण के लिए 84 माह है।

- तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों के लिए प्रति वर्ष **पुस्तकों और स्टेशनरी** वस्तुओं की खरीद हेतु **₹10,000** तथा **लैपटॉप** की खरीद के लिए **₹35,000** की राशि निर्धारित की गई है।
- आवेदकों की पढ़ाई अथवा मोराटोरियम अथवा ऋण वापसी की अवधि के दौरान यदि मृत्यु होती है, तो वैसी स्थिति में उनके अभिभावकों द्वारा जो शिक्षा ऋण की राशि वापस की जाती थी उसे ब्याज सहित पूर्ण ऋण राशि अथवा अधिशेष ऋण राशि को माफ कर दिया गया है।
- जो छात्र छात्रावास में नहीं रहते, उनके लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जीवन–यापन खर्च हेतु प्रति माह **₹5,000** (पाठ्यक्रम अवधि में अधिकतम ₹60,000 प्रति वर्ष) तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि शहर की श्रेणी के आधार पर तय की जाती है।
- अब तक **4,04,167** छात्रों को सफलतापूर्वक ऋण वितरित किया गया है, जिसकी कुल राशि **₹8,149.56** करोड़ है।

<u>मुख्यमंत्री कन्या उत्थान प्रोत्साहन योजना</u>

- मुख्यमंत्री कन्या (स्नातक) प्रोत्साहन योजना .बिहार सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि उनकी पढ़ाई में कोई बाधा न आए और वे आत्मनिर्भर बन सकें।
- योजना अंतर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि **25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000** रुपये किया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्या (स्नातक) प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष **2025–26** में कुल **रु० 990 करोड़ (नौ सौ नब्बे करोड़) कुल 1,98,000 (एक लाख अंठानवे हजार) छात्राओं को भुगतान किया गया।**

- अब तक **8,67,536** बालिकाओं को सफलतापूर्वक कुल राशि **₹3,614.92** करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

अन्य योजनाओं से संबंधित उपलब्धियाँ

- माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में **बक्सर में संगीत महाविद्यालय** की स्थापना की जा रही है।

- माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान **विभिन्न अनुमंडल में 10 डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने** की घोषणा की गई। इसमें से **07 डिग्री महाविद्यालय में भवन निर्माण** कार्य शुरू हो चुका है व शेष 03 डिगी महाविद्यालयों में योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है।

- सभी विश्वविद्यालयों में सत्र लगभग नियमित हो गए हैं।

- विश्वविद्यालयकर्मियों को **वेतन एवं पेंशन** का भुगतान **प्रति माह ससमय** हो रहा है।

- पटना शहरी क्षेत्र के सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के **छात्रावासों के जीर्णोद्धार** हेतु कुल **30 करोड़ रूपये** की योजना स्वीकृति तथा कार्य प्रारंभ।

- लगभग **244 करोड़** रूपये संबद्ध **महाविद्यालयों को परीक्षाफल आधारित अनुदान** की राशि दी गई है।

- विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन में सहयोग हेतु विश्वविद्यालयों को कन्करेंट ऑडिटर्स एवं अन्य ऑडिटर्स की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

- **PM-USHA** के अंतर्गत बिहार राज्य के लिए कुल 385 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

- **मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी** (MERU) के तहत दो विश्वविद्यालयों (पटना विश्वविद्यालय और ललित

नारायण मिथिला विश्वविद्यालय) को 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए ।

- जेंडर इनक्लूजन एंड इक्विटी इनिशिएटिव (GIEI) के लिए पाँच जिलों के पाँच कॉलेजों को 10.10 **करोड़** रुपये,
- तीन विश्वविद्यालयों को सशक्तिकरण हेतु 20.20 करोड़ रुपये, और बिहार के 19 फोकस जिलों में 15 कॉलेजों को 5.5 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है।

Samarth ERP

- समर्थ एक डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म या ERP सिस्टम है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था,जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) को एक डिजिटल ढांचे के माध्यम से योजना, प्रबंधन, सेवा वितरण और छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए सेवाओं की निगरानी में सक्षम बनाना है। राज्य के विभिन्न विश्ववद्यालयों में Samarth ERP लागू किया जा रहा है, जिससे :–
- छात्र–छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया आसान होगी।
- परीक्षा–फल प्रकाशन प्रक्रिया आसान होगी।
- सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का वेतन/पेंशन भुगतान ऑनलाइन हो सकेगा।
- शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आयेगी।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य (अभिलेखों के संधारण सहित) ऑनलाइन एवं पारदर्शिता के साथ हो सकेंगे।
- मान्यता (एफलिशियन) की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- बजट की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जायेगी।

INFLIBNET & ONOS

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों को ई–पुस्तकालय सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु:–

- यूजीसी के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (INFLIBNET) बिहार के 15 राज्य विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया है जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यथा - शोध प्रबंधों, पत्रिकाओं, ई–पुस्तकों आदि की ऑनलाइन उपलब्धता होंगी जिससे बिहार के छात्र, शोधकर्ता, संकाय सदस्य और संपूर्ण विद्वान समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं।
- इसके अन्तर्गत One Nation One Subscription (ONOS) की व्यवस्था है, जिसके तहत 13 हजार से अधिक राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकायें ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं जिसका लाभ शैक्षणिक संस्थानों के छात्र, शोधकर्ता शिक्षकों को प्राप्त हो रहा है।

18. **BSEIDC (**बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम**)**

- **बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (BSEIDC)** द्वारा स्कूल भवन कक्षाऐं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाऐं और अन्य सुविधाओं के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं रख–रखाव का कार्य किया जाता है। योजना सहित **556 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण, 2820 नया विद्यालय भवन का निर्माण, 140 बालिका छात्रावास, 20 मॉडल स्कूल, 17 डिग्री कॉलेज, 38 शिक्षा भवन आदि** योजना सहित **लगभग 3776 परियोजनाओं में से लगभग 2045 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है।** वित्तीय वर्ष 2025–26 में 2245.11 करोड़ रूपेय का आवंटन आधारभूत संरचना विकास हेतु आवंटित किया गया है।
- शिक्षा विभाग अंतर्गत दिनांक 20.09.2025 को 958.79 करोड़ की लागत से 259 परियोजनाओं का उद्घघाटन एवं 72 योजनाओं

का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलो से किया गया था

समझौता ज्ञापन (MoU)

S.No.	Name of Organization	Target Group	Activity to be carried out
1	**Physics Wallah (PW)**	**KGBVs** एवं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के कक्षा 9–12	**IIT-JEE** एवं **NEET** की तैयारी
2	**Adobe Education Express**	कक्षा 6–12 के विद्यार्थी और शिक्षकों को मुफ्त **Adobe Express Premium access**	डिजिटल कंटेंट, नियमित प्रशिक्षण और क्रिएटिव गतिविधियाँ उपलब्ध कराकर डिजिटल क्रिएटिविटी और **AI** स्किल्स को बढ़ावा देना।
3	**Social Network India (CSR for Colgate)**	कक्षा 6–10 के विद्यार्थी	बच्चों में मौखिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण के प्रति जागरूकता लाने हेतु स्कूल स्तर पर कार्य करना।
4	**Piramal Foundation-Secondary Eduction**	कक्षा **9–12** के विद्यार्थी	**Skill Education , Employability Skills, Life Skills, Retention vkSj Transition** सुधारते हुए एक बेहतर **School Environment** विकसित करनाय छात्रों को **Community – based Projects** से जोड़ना।
5	**Piramal Foundation-SCERT**	**6–12** के शिक्षक	**Training Modules** और **Capacity Building** के माध्यम से जिला स्तर पर **Master Facilitators** तैयार करना।
6	**SATHEE (Self-Assessment, Test, and Help for Entrance Examinations) – IIT Kanpur**	कक्षा 10–12 के विद्यार्थी	छात्रों को सुलभ, बहुभाषी और निरूशुल्क डिजिटल शिक्षा, वीडियो लेक्चर्स, अध्ययन सामग्री, **AI** –आधारित टेस्टिंग और मेंटरशिप जैसी सुविधाएँ प्रदान करना।
7	**Educate Girls**	ड्रॉपआउट छात्रों के लिए	ड्रॉपआउट छात्रों के नामांकन, तकनीकी–सामग्री सहयोग और छात्राओंध्महिलाओं के सशक्तिकरण
8	**Sightsavers India**	दृष्टिबाधित बच्चे	दृष्टिबाधित बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा, ब्रेल सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण और स्क्रीनिंग सुविधा प्रदान करना।

9	**Bharat Innovation Global (BIG)**	कक्षा 8 के विद्यार्थी	**National Means-cum-Merit Scholarship (NMMS)** परीक्षा की तैयारी
10	**Freadom Edu Services Pvt. Ltd.**	कक्षा 6–8 के विद्यार्थी	अंग्रेजी भाषा दक्षता, पठन क्षमता, उच्चारण एवं संवाद कौशल का विकास।
11	**Udayan Shalini Fellowship (USF)**	पटना के चयनित सरकारी विद्यालयों के 30 मेधावी छात्राओं के हेतु	छात्रवृत्ति, करियर गाइडेंस और मेंटोरिंग सुविधा उपलब्ध कराएगा।
12	**Going to School Fund**	कक्षा 7–12 के विद्यार्थी	जीवन कौशल, डिजिटल स्किल, **STEM** शिक्षा एवं उद्यमिता का विकास।
13	**Family Tree Foundation**	सरकारी विद्यालय	सरकारी विद्यालय परिसरों में वृक्षारोपण, पर्यावरण शिक्षा और ग्रीन स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देना ।
14	**PRAYOG**	चयनित विद्यालय	चयनित विद्यालयों में समृद्ध पुस्तकालयों की स्थापना, पठन संस्कृति, और सामुदायिक पठन गतिविधियों को सशक्त करना
15	**INFLIEBNET**		बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों को ई–पुस्तकालय सेवाओं का लाभ प्रदान करने हेतु एक अथक शुरुआत की गयी है जिसके अंतर्गत यूजीसी के सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क (**INFLIBNET**), बिहार के 15 राज्य विश्वविद्यालयों एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर वर्ष 2022 में किया गया जिसके अन्तर्गत उच्च शिक्षा से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की 8 सुविधाएं उपलब्ध है जिससे बिहार के छात्र, शोधकर्ता, संकाय सदस्य और संपूर्ण विद्वान समुदाय लाभवंतित होंगे । शोध को उच्च स्तरीय करने के सपने को साकार करने हेतु अब INFLIBNET द्वारा **ONOS** की शुरूवात की जा रही है